- 19th Year
- Issue: 208
- 01.12.2025 (MONDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

नई एफआईआर से सोनिया-राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, आपराधिक साजिश के लगे आरोप

नई दिल्ली ३०/११ (संवाददाता): नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। रविवार को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इन दोनों सीनियर नेताओं के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की है। इस एफआईआर में उन पर मामले में आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इस नई एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा चार और लोगों, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी और एक अज्ञात व्यक्ति का नाम हैं। इसके अलावा, तीन कंपनियों एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यंग इंडियन और

डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आपराधिक साजिश के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार की पेरेंट कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर धोखे से कब्जा किया गया।यंग इंडियन एक नॉट–फॉर–प्रॉफिट कंपनी थी, जिसमें गांधी परिवार की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। एफआईआर के अनुसार, डोटेक्स मर्चेंडाइज (कोलकाता की एक कथित शेल कंपनी) ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपये दिए। आरोप है कि इस लेनदेन का इस्तेमाल करते हुए यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपये दिए और AJL पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ।श्रस के पास उस समय लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। यह एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय की एक शिकायत पर आधारित है, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की थी। यह मामला 2012 का है, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हुए केस दायर किया था। नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। AJL, जो नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करती थी, 2008 में पैसे की तंगी के चलते बंद हो गई। कंपनी पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज था। इस कर्ज को चुकाने में मदद के लिए, कांग्रेस पार्टी ने एजीएल को 90 करोड़ रुपये का लोन दिया।

सुभद्रा योजना में 17 लाख नए लाभार्थी जुड़े: पार्वती परिडा

भुवनेश्वर ३०/११ (संवाददाता): ओडिशा विधानसभा में बोलते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रावती परिदा ने कहा कि सुभद्रा योजना में 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है। कुल 17,83,251 महिलाओं ने एनरोल किया है, जबकि 9,36,283 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए। एनरोल हुई महिलाओं में से 7,51,479 को तीनों इंस्टॉलमेंट मिल चुकी हैं। इसके अलावा, 1,03,89,801 महिलाओं को पहली इंस्टॉलमेंट और 1,01,92,724 को दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली है, परिदा ने सदन को बताया। खास बात यह है कि 1 नवंबर, 2025 को ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना के नए बेनिफिशियरी के लिए एप्लीकेशन फिर से खोल दिए हैं।

मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे ने सामूहिक विवाह में की शादी

भोपाल ३०/११ (संवाददाता): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव ने रविवार को उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे एक सामूहिक विवाह समारोह में डॉ. इशिता पटेल के साथ सात फेरे लिए। इस जोड़े ने सादगी और फिजूलखर्ची से बचने का संदेश देते हुए, 21 दूसरे जोड़ों के साथ एक ही कार्यक्रम में शादी की। परिवार ने कहा कि इस आयोजन का मकसद शादियों में सादगी को बढ़ावा देना और अनावश्यक खर्चों से बचना था। समारोह में पारंपरिक रंग देखने को मिले। दूल्हे घोड़ों पर सवार होकर आए, जबकि दुल्हनें सजी हुई गाड़ियों में बैठी थीं। भव्य बारात और सांस्कृतिक आकर्षणों ने धन–दौलत के दिखावे की जगह

ले ली। शादी के निमंत्रणों में भी महंगे तोहफों या दिखावटी सेटिंग्स को स्पष्ट रूप से हतोत्साहित किया गया था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि सामूहिक शादी करने का फैसला मुख्यमंत्री का सोचा–समझा कदम था ताकि सामाजिक बराबरी और शादी के खर्चों पर रोक का एक उदाहरण पेश किया जा सके। बाबा महाकाल, भगवान श्री गोपाल कृष्ण की असीम कृपा और पूज्य माताजी– पिताजी के आशीर्वाद से आज सुपुत्र डॉ. अभिमन्यु और सौभाग्यवती डॉ. ईशिता सहित कुल 21 नवयुगल सामूहिक विवाह समारोह में परिणय सूत्र में बंधे। सामूहिक शादी में आध्यात्मिक गुरुओं से लेकर कई राजनीतिक हस्तियों ने भी शिरकत की, जिससे यह समारोह एक अनोखा और यादगार इवेंट बन गया। सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक टीमों ने आयोजन स्थल के आसपास कड़े इंतजाम किए थे।

तमिलनाडू में रेड अलर्ट जारी, भारी बारिश से तीन लोगों की मौत

चेन्नई ३०/११ (संवाददाता): उत्तरी तमिलनाडु के कई जिलों में साइक्लोन शदितवाहश के कारण भारी बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त– व्यस्त हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आस–पास के दक्षिणी आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तूफान लगातार तट के करीब से गुजर रहा है। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के के एसएसआर रामचंद्रन ने पुष्टि की है कि चक्रवात से संबंधित बारिश की घटनाओं में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। आईएमडी के अनुसार, साइक्लोन शदितवाहश अभी भी दक्षिण–पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर, उत्तरी तमिलनाडु– पुडुचेरी तट के पास बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि यह

सिस्टम पिछले 6 घंटों में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लगभग उत्तर की ओर बढ़ा और रविवार सुबह देर से उसी इलाके में स्थिर हो गया।साइक्लोन के केंद्र से उत्तरी तमिलनाडु–पुडुचेरी तटों की सबसे कम दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। यह कुड्डालोर से लगभग 100 किमी पूर्व– दक्षिणपूर्व और चेन्नई से 170 किमी दक्षिण–दक्षिणपूर्व में केंद्रित है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान तूफान के उत्तरी तमिलनाडु–पुडुचेरी तटों के समानांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु–पुडुचेरी इलाके में 60–70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेन्नई, कांचीपुरम और पुडुचेरी समेत 15 से अधिक जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हालतरू कावेरी डेल्टा क्षेत्र, खासकर रामनाथपुरम और नागपट्टिनम जिलों में गंभीर जलभराव की सूचना मिली है। रामेश्वरम और नागपट्टिनम जैसे तटीय शहरों के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं।

8.16 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए

भुवनेश्वर ३०/११ (संवाददाता): ओडिशा सरकार ने राज्य में चल रहे ई केवाईसी ड्राइव के दौरान 8.16 लाख से ज्यादा घोस्ट राशन कार्ड कैंसिल कर दिए हैं और सरकारी खजाने के लिए हर साल 210 करोड़ रुपये बचाए हैं। फूड सप्लाई और कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर कृष्ण चंद्र पात्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में अपोजिशन बीजद और कांग्रेस के लाए गए एडजर्नमेंट मोशन नोटिस का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। मिनिस्टर ने कहा कि 17 महीने पहले ठश्रच के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने ई केवाईसी ड्राइव शुरू की थी। इस प्रोसेस के तहत, 6.95 लाख से ज्यादा घोस्ट कार्ड का पता लगाया गया और उन्हें कैंसिल कर दिया गया। अपोजिशन के उन आरोपों का जवाब देते हुए कि राज्य सरकार ने म–झल्ब ड्राइव के तहत कई असली बेनिफिशियरीज के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए हैं, मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे एक भी व्यक्ति को लिस्ट से हटाया नहीं गया है।

मौजूदा दौर में राजनीति अर्थव्यवस्था पर हावी होती जा रही है-जयशंकर

नई दिल्ली ३०/११ (संवाददाता): विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को कहा कि मौजूदा समय में राजनीति अर्थव्यवस्था पर तेजी से हावी होती जा रही है। जयशंकर यहां आईआईएम– कलकत्ता के परिसर में 'डॉक्टरेट' की

मानद उपाधि मिलने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा दौर है जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था पर हावी होती जा रही है... और यह कोई मजाक की बात नहीं है। जयशंकर ने यह भी कहा कि चीन ने लंबे समय तक अपने ही नियमों के अनुसार चीजें की है और वह अब भी ऐसा ही कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस परिस्थिति में, अन्य देश इस बात को लेकर अस्पष्ट हैं कि दिख रही प्रतिस्पर्धा या सौदेबाजी पर ध्यान देना चाहिये या नहीं।

६५ लाख के २७ इनामी सहित ३७ नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा ३०/११ (संवाददाता): छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार को 65 लाख रुपए के कुल 27 इनामी सहित 37 हार्डकोर नक्सलियों ने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। सभी ने डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में अधिकारियों के सामने औपचारिक आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित कैडरों में चार 8 लाख, एक 5 लाख, और कई 2 लाख व 1 लाख के इनामी शामिल हैं। इनमें कंपनी नंबर–6, कंपनी नंबर–10, प्लाटून–16, आमदई एरिया कमेटी और इंद्रावती एरिया कमेटी जैसे कोर नक्सली ढांचे के सक्रिय

सदस्य हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, जो एसजीसीएम कमलेश की बॉडीगार्ड और डीवीसीएम निर्मला की गार्ड रह चुकी हैं। इन आतंकियों पर 2019–2024 के बीच कई बड़ी वारदातें दर्ज हैं। इनमें 2020 में मिनपा में टीसीओसी टीम पर हमला (26 जवान शहीद, 20 घायल, हथियार लूट), 2024 में गोबेल–थुलथुली जंगल में पुलिस पार्टी पर फायरिंग और सड़कें खोदना, पेड़ गिराना, बंद सप्ताह में बैनर–पोस्टर लगाना शामिल हैं। आत्मसमर्पण समारोह में डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, डीआईजी सीआरपीएफ राकेश चौधरी, एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय, कमांडेंट 111, 230 व 80वीं वाहिनी सीआरपीएफ सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आईजी बस्तर सुंदरराज पी. ने बताया कि पूना मारगेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) अब बस्तर में स्थायी शांति की सबसे मजबूत पहल बन चुकी है। सिर्फ 20 महीनों में दंतेवाड़ा में 165 इनामी सहित 508 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। पूरे बस्तर रेंज में लोन वर्राटू अभियान के तहत 333 इनामी सहित 1,160 नक्सली मुख्यधारा में लौट चुके हैं। आत्मसमर्पित सभी नक्सलियों को तत्काल 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत इन्हें कौशल प्रशिक्षण, कृषि भूमि, मकान और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

कांग्रेस ने गिनाए बिहार चुनाव में मिली शिकस्त के पीछे के मुख्य बिंदु

नई दिल्ली ३०/११ (संवाददाता): कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की बिहार इकाई के नेताओं के साथ राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की, जहाँ हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में इस पुरानी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह बैठक खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई। बैठक के दौरान, बिहार से पार्टी के प्रमुख नेताओं, जिनमें कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु शामिल थे, ने भाग लिया। गौरतलब है कि 2025 के बिहार चुनावों में पार्टी की करारी हार पर चर्चा के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा

की गई यह दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है।

कांग्रेस नेताओं ने बिहार चुनाव में हार के लिए टिकट वितरण में देरी, पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह और मतभेदों को जिम्मेदार ठहराया।

नेताओं ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की महिलाओं के लिए 10,000 रुपये की प्रोत्साहन योजना को भी जिम्मेदार ठहराया। 61 सीटों पर चुनाव लड़कर, इस पुरानी पार्टी ने सिर्फ छह सीटें जीतीं, और उसका स्ट्राइक रेट 10 प्रतिशत से भी कम रहा। इसके गठबंधन सहयोगी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा और उसने 143 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 25 सीटें जीतीं। कुल मिलाकर, महागठबंधन ने 243 सीटों में से सिर्फ 35 सीटें जीतीं।भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स वादी– लेनिनवादी) (लिबरेशन) जैसे छोटे सहयोगियों ने दो सीटें जीतीं।

संसद का शीतकालीन सत्र आज से, हंगामेदार होने कीसंभावना

नई दिल्ली ३०/११ (संवाददाता):संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले, रविवार को केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। संसद भवन में हुई इस बैठक में, विपक्ष ने कई अहम मुद्दे उठाए जिन्हें वे सदन के अंदर उठाना चाहते हैं।

इनमें वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हाल ही में दिल्ली में हुए बम धमाके और विदेश नीति से जुड़ी मुख्य चिंताएं शामिल हैं। वहीं, सरकार ने अपनी कानूनी प्राथमिकताएं बताईं और सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा।

हालांकि, बैठक के बाद, कांग्रेस ने सत्र की छोटी अवधि (केवल 15 बैठकें) का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार श्संसद को पटरी से उतारने पर आमादाश लग रही है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 19 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी, जो आम तौर पर होने वाली 20 बैठकों से काफी कम हैं और यह हाल के सालों के सबसे छोटे सत्रों में से एक है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक से पहले सभी से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा, श्यह सर्दियों का मौसम है, हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई ठंडे दिमाग से काम करेगा और गरमागरम बहस से बचेगा... शांत दिमाग से काम करने से देश को फायदा होगा। सरकार इस सत्र में कुल 14 बिल पेश करने की तैयारी में है, जिनमें कुछ बड़े और ढांचागत सुधार वाले बिल शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा बिल, 2025 – इसका उद्देश्य परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025 – यह यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक केंद्रीय आयोग बनाने का प्रस्ताव करता है, जिसका मकसद शैक्षणिक मानकों को सुधारना है।दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025– यह दिवालियापन से जुड़े कानूनों में बदलाव करेगा।राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025रू यह हाईवे विकास के लिए तेज और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण को आसान बनाएगा। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, सेबी और आर्बिट्रेशन एक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी सूचीबद्ध हैं। सत्र में राजनीतिक टकराव और बड़े कानूनी सुधारों का मिश्रण देखने को मिल सकता है।

विविध समाचार

पूर्वांचल की सियासत में बड़ा बदलाव, टकराव भुलाकर फिर दोस्त बने योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह

लखनऊ ३०/११ (संवाददाता):उज़र प्रदेश की राजनीति में रिश्तों के उतार-चढ़ाव का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन जब बात दो बड़े और प्रभावशाली नेताओं—मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की हो, तो यह केवल व्यक्ति-विशेष की नहीं, बल्कि सज़ा के समीकरणों की कहानी बन जाती है। कभी गहरे दोस्त माने जाने वाले ये दोनों नेता बीते कुछ वर्षों में खामोश टकराव और आपसी दूरियों के प्रतीक बन चुके थे। लेकिन हालिया मुलाकात और गर्मजोशी ने इस रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया है, जोकि इस समय सुर्खियों में है।

हम आपको याद दिला दें कि 2000 के दशक की शुरुआत में जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से नई पीढ़ी के तेजतर्रार नेता के रूप में उभर रहे थे और बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या व गोंडा क्षेत्र के ताकतवर ठाकुर नेता बन चुके थे, तब इन दोनों के बीच मजबूत संबंध थे। इनका जातीय समीकरण, हिंदुत्व की समान विचारधारा और पूर्वांचल पर नियंत्रण की महत्वाकांक्षा, इन सबने इन्हें एक स्वाभाविक राजनीतिक जोड़ी बना दिया था। योगी के लिए बृजभूषण जैसे पुराने राजनीतिक %मैदानी% नेता का समर्थन ज़रूरी था, तो वहीं बृजभूषण के लिए योगी की धार्मिक छवि एक शक्ति थी। हम आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय राजनीति के उस चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने इलाके में निर्विवाद दबदबे के लिए जाने जाते हैं। छह बार के सांसद और एक प्रभावशाली ठाकुर नेता के रूप में उन्होंने पूर्वांचल में एक खास राजनीतिक क्षेत्र गढ़ा है। उनका असर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और अयोध्या तक फैला है। लेकिन 2022 के बाद यह दोस्ती धीरे-धीरे दरकती नज़र आई। इसके पीछे कई

कारण माने गए। जैसे- योगी आदित्यनाथ बतौर मुज़्यमंत्री एक केंद्रीकृत सज़ा मॉडल बना रहे थे, जिसमें स्वतंत्र क्षेत्रीय क्षत्रपों की भूमिका सीमित होती जा रही थी। बृजभूषण जैसे नेता, जो वर्षों से अपने इलाके में %स्वतंत्र सज़ा केंद्र% बने हुए थे, इस बदलाव से असहज थे। इसके अलावा, योगी सरकार की शैली कई पुराने नेताओं के लिए चुनौती बन गई। बृजभूषण समर्थकों का आरोप था कि प्रशासन उन्हें और उनके समर्थकों को निशाना बना रहा है। वहीं योगी के खेमे को लगता था कि बृजभूषण पार्टी अनुशासन से बाहर जाकर काम करते हैं। इसके अलावा, महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद भाजपा नेतृत्व के लिए यह सवाल बन गया था कि उन्हें कितना समर्थन दिया जाए।

योगी सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट दूरी बनाए रखी। लेकिन अब तीन साल की दूरी के बाद योगी और बृजभूषण की हालिया मुलाकात ने राजनीति में हलचल मचा दी है। यह सिर्फ व्यक्तिगत मेल-मिलाप नहीं, बल्कि एक गहन राजनीतिक संदेश है। दरअसल भाजपा को उज़र प्रदेश के पूर्वांचल में एक बार फिर एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। सपा, कांग्रेस, और बसपा नए सिरे से यहां आधार तलाश रहे हैं। ऐसे में योगी और बृजभूषण का साथ आना भाजपा के लिए ताकत का प्रदर्शन है। हम आपको यह भी बता दें कि यह मुलाकात संभवत- भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से हुई है।

इसके अलावा, दोनों नेता ठाकुर समुदाय से आते हैं, यदि यह दोनों साथ चलते हैं तो पूरे पूर्वांचल में इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बना सकते हैं। हम आपको बता दें कि उज़र प्रदेश विधानसभा चुनाव भले दूर हो, लेकिन भाजपा में अभी से ही आंतरिक समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। ऐसे में योगी और बृजभूषण की दोस्ती भविष्य के भीतरू संघर्षों को टालने का माध्यम भी हो सकती है। देखा जाये तो योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की यह दोस्ती भाजपा के अंदर शक्ति-संतुलन, क्षेत्रीय सशक्तिकरण और जातीय समीकरणों को साधने की कवायद भी है। उज़र प्रदेश की राजनीति में यह दोस्ती सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो राजनीतिक संस्कृतियों—%संगठित सज़ा% और %स्थानीय ताकत% के बीच नए गठबंधन की शुरुआत है।

योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात के कुछ और भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में बृज भूषण के विधायक बेटे की उज़र प्रदेश के उपमुज़्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से हुई मुलाकात भी सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि उज़र प्रदेश मंत्रिमंडल में होने वाले संभावित फेरबदल में बृज भूषण के बेटे को जगह दी जा सकती है। यह दिखाता है कि भाजपा अपने पुराने और क्षेत्रीय क्षत्रपों को साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है। वहीं योगी आदित्यनाथ, जो अज़्सर अपने %नैतिक% और %कठोर% प्रशासनिक रुख के लिए जाने जाते हैं, अब सियासी यथार्थवाद के साथ भी संतुलन बनाते दिख रहे हैं।

जनसुराज के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, प्रशांत किशोर ने साधा सरकार पर निशाना

पटना ३०/११ (संवाददाता):जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हजारों समर्थकों पर बुधवार को बिहार की राजधानी में पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, जब वे नीतीश कुमार सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए विधानसभा मार्च करने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जनता का यह ज्ञापन मुज़्यमंत्री को देना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों में उन्होंने 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपये देने का वादा किया था, लेकिन आज तक एक भी परिवार को एक भी रुपया नहीं मिला।

प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार मिलने से इनकार कर रही है, और जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे नहीं मिलता, हम यहीं बैठे रहेंगे। लड़ाई अभी शुरू हुई है। अभी तीन महीने बाकी हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। वे विधानसभा में और पुलिस के पीछे नहीं छिप सकते। हम उन्हें ऐसा जवाब देंगे कि पूरा बिहार देखेगा। हम बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उनके घर में घेर लेंगे, और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी।

पटना की एसपी दीक्षा ने बताया कि उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, और उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा, इन लोगों से बातचीत चल रही है। अगर वो एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर अपनी माँगें बताने को तैयार हैं, तो हम उन्हें सामने रखेंगे। अगर उनकी तरफ़ से कोई और उल्लंघन हुआ, तो कार्रवाई की जाएगी। इस नई पार्टी ने घोषणा की थी कि यह मार्च दोपहर के आसपास होगा, जिसमें राज्य के एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर होंगे, जो किशोर द्वारा कुछ महीने पहले शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान के तहत एकत्र किए गए थे।जन सुराज पार्टी के समर्थक तज़्तियाँ लिए हुए थे जिन पर हस्ताक्षर अभियान के तीन मुद्दे थे। इनमें से एक मुद्दा यह था कि बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के बाद गरीब परिवारों को ?2 लाख की सहायता देने की घोषणा की थी, जबकि इस सर्वेक्षण में आबादी के एक बड़े हिस्से की आर्थिक स्थिति बेहद खराब पाई गई थी।

हिमाचल प्रदेश में कई स्कूलों को बम की धमकी वाला संदेश मिला, कई टीम बम निरोधक दस्तों के साथ स्कूलों में पहुंचीं

शिमला ३०/११ (संवाददाता): पिछले काफी समय से लगातार बम विस्फोट करने की धमकियों भरे ईमेल और संदेशआ रहे हैं। गोल्डन टेज़्पल से लेकर कई बड़े बड़े स्कूलों तक को बम की धमकियां दी गयी। अब ताजा मामला हिमाचल प्रदेश से आया है। हिमाचल प्रदेश के कई स्कूलों को बुधवार सुबह बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों में दहशत फैल गई। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बाद में ये धमकियां अफवाह निकलीं। पुलिस ने बताया कि धमकियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस की कई टीम बम निरोधक दस्तों के साथ स्कूलों में पहुंचीं। खबर फैलते ही घबराए अभिभावकों ने अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में पूछताछ करने के लिए स्कूलों को फोन किया और अपने अपने बच्चों को लेने पहुंचे। कुछ स्कूलों में छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

पुलिस अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि सभी स्कूलों के परिसरों की गहन तलाशी ली गई और बम निरोधक दस्तों की टीम ने गहनता से निरीक्षण किया। हालांकि, जांच में कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला। ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि पुलिस उन अन्य राज्यों के अपने समकक्षों के साथ भी समन्वय कर रही है, जहां के स्कूलों को इसी तरह की धमकियां मिली थीं। उज़र प्रदेश के आगरा में दो निजी स्कूलों को भी बुधवार सुबह बम की धमकी वाले ईमेल मिले। इससे पहले, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय परिसर, उपायुक्तों के कार्यालयों और राज्य सचिवालय को बम की धमकियां मिली थीं, लेकिन ये सभी अफवाह निकलीं। इससे पहले आज ही आगरा और मेरठ में निजी स्कूलों को बुधवार को बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल मिले जिसके बाद बम निरोधक और श्वान दस्ते ने स्कूलों के परिसर की गहन तलाशी ली लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस ने यह जानकारी दी। आगरा के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विनायक भोसले ने बताया कि शहर के श्री राम स्कूल और ग्लोबल स्कूल को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। उन्होंने कहा, ''बम निरोधक दस्ते और श्वान दस्ते ने दोनों स्कूलों की गहन तलाशी ली। किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।'' अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के बाद विद्यार्थी अपनी पढ़ाई-लिखाई में जुट गए। साइबर प्रकोष्ठ ने इन ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू की है। भोसले ने कहा, ''प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये ईमेल कोलकाता से आए थे। दोषियों का पता लगाने के लिए गहन जांच जारी है।

विपक्षी दलों के सांसदों ने काली कमीज पहनकर और काली पट्टी बांधकर संसद परिसर में किया प्रदर्शन

नयी दिल्ली ३०/११ (संवाददाता): विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को राज्यसभा की बैठक शुरु होने के कुछ ही देर बाद दोपहर बारह बजे तक स्थगित कर दी गई। और लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। हंगामे की वजह से सदन में शून्यकाल नहीं हो पाया। उच्च सदन की बैठक शुरु होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर भी विपक्ष का हंगामान जारी रहा। विपक्षी 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्ज़्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के कई

घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कई सांसदों ने काली कमीज पहन रखी थी, तो कई ने बांह पर काली पट्टी बांध रखी थी। संसद के 'मकर द्वार' के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य सांसद शामिल हुए। उन्होंने 'मोदी सरकार हाय-हाय' और 'मोदी सरकार डाउन-डाउन' के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने यह भी कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के विषय पर सदन में कब चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, ''बिहार में जो प्रक्रिया (एस आई आर) शुरू हुई और यह पूरे देश में फैलेगी। इसका मकसद यह है कि जो भाजपा को वोट नहीं करते, उनका मताधिकार छीना जाएगा। इस वोटबंदी का हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे।' उन्होंने कहा कि एसआईआर और पहलगाम के मामले पर ससंद में कब चर्चा होगी, उस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।

संसद के नहीं चलने से सबसे ज्यादा फायदा सरकार को होता है-डेरेक ओ'ब्रायन

नयी दिल्ली३०/११ (संवाददाता): बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अज़्यास पर चर्चा की विपक्ष की मांग और लोकसभा व राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे पर राजनीतिक गतिरोध के बीच, सरकार ने आज के एजेंडे में छह विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। इन छह विधेयकों में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025, जिसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएँ व कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं। लेकिन संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। किसी भी तरह की कोई बहस नहीं हो पा रही है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। विपक्ष के इस व्यवहार पर उठ रहे सवालों के बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने बुधवार को कहा कि जब संसद नहीं चलती है तो सबसे ज्यादा फायदा सरकार को होता है। सोशल मीडिया मंच 'एज़्स' पर एक पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मानसून सत्र के दो दिन ''बेकार'' चले गए और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिज़्मेदार ठहराया। ओ'ब्रायन ने कहा, ''केंद्र सरकार ने संसद के दो दिन व्यर्थ गंवा दिए। जब संसद नहीं चलती है, तो फायदा किसे होता है? सज़ा में बैठी सरकार को।''

उन्होंने कहा, ''सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है, संसद जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जब संसद काम नहीं करती है तो सरकार किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होती।'' उन्होंने अपने ज़्लॉग पोस्ट से एक लेख भी साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि मानसून सत्र का कुल समय 190 घंटे का है जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत सरकारी कामकाज के लिए है। ओ'ब्रायन ने कहा कि प्रश्नकाल के लगभग आधे प्रश्न और शून्यकाल के आधे नोटिस विपक्षी सांसदों द्वारा दायर किए जाते हैं, जिससे विपक्षी सदस्यों के पास सार्वजनिक महत्व के प्रश्न और मुद्दे उठाने के लिए कुल 31 घंटे का समय होता है।

भारत-पाकिस्तान के बीच का टकराव परमाणु युद्ध में बदल सकता था...डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया अपना दावा

नयी दिल्ली ३०/११ (संवाददाता): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हालिया भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने में मदद का श्रेय लिया और कहा कि भारत - पाकिस्तान के बीच टकराव का अंत संभवत: परमाणु युद्ध में हो सकता था। व्हाइट हाउस में एक स्वागत समारोह में ट्रंप ने कहा, हमने भारत और पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच युद्ध रोके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान पांच विमानों को गिराया गया और उन्होंने इस ''युद्ध'' को रुकवाया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष ''परमाणु युद्ध में तज़्दील हो सकता'' था। उन्होंने 'व्हाइट हाउस' (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ''हमने भारत और पाकिस्तान तथा कांगो

लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच युद्ध रुकवाए।'' ट्रंप ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव का जिक्र करते हुए कहा, ''उन्होंने पांच विमान मार गिराए।... मैंने उन्हें फोन किया और कहा, 'सुनो, अब और व्यापार नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका कोई भला नहीं होगा।' ... वे दोनों शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश हैं और कौन जानता है कि इसका ज़्या नतीजा होता। मैंने इसे रुकवा दिया।'' अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की पूरी परमाणु क्षमता को नष्ट कर दिया और कोसोवो एवं सर्बिया के बीच संघर्ष भी रुकवाया। ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने व्यापार के माध्यम से भारत एवं पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को रुकवाया है। उन्होंने पिछले शुक्रवार को पहली बार कहा था कि लड़ाई के दौरान ''पांच विमान मार गिराए गए थे।' इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की शीर्ष राजनयिक ने भी मंगलवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद की।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका विवादों में मध्यस्थता करने और दुनिया भर में शांतिपूर्ण समाधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यवाहक अमेरिकी प्रतिनिधि राजदूत डोरोथी शिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित बहुपक्षवाद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान विषय पर खुली बहस में कहा, ''अमेरिका दुनिया भर में विवादों में शामिल पक्षों के साथ, जहां तक संभव हो, शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए काम करना जारी रखता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इसहाक डार की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में शिया ने कहा कि पिछले तीन महीनों में ही अमेरिकी नेतृत्व ने ''इजराइल और ईरान के बीच, कांगो और रवांडा के बीच तथा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में सफलता प्राप्त की है।''संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने यूएनएससी (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) चैंबर में अपने बयान में पहलगाम आतंकवादी हमले के बारे में बात की। इस हमले की जिज़्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने ली है। पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

बारिश के मौसम में रोज खाएं 1 चम्मच शहद

शहद गुणों की खान होता है। इसका इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। क्या आप जानती हैं कि अगर मानसून में आप रोज एक चम्मच शहद खाएंगी, तो इससे आपको अनगिनत फायदे मिल सकते हैं।

मानसून में कई बीमारियों का खतरा रहता है। बदलते मौसम के बीच, बुखार, जुकाम, सिरदर्द, जोड़ों का दर्द और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें काफी आम रहती हैं। ऐसे में सेहतमंद रहने के लिए डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। बारिश में सही खान-पान बहुत जरूरी है ताकि इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। जहां इम्यूनिटी कमजोर होने पर बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। वहीं, इम्यूनिटी मजबूत होने पर इंफेक्शन्स का खतरा कम रहता है। सेहतमंद रहने के लिए, बारिश में डाइट में कई खास चीजों को शामिल करना चाहिए। आयुर्वेद मानसून में रोज 1 चम्मच शहद खाने की सलाह देता है। जी हां, अगर मानसून में आप रोज एक चम्मच शहद खाएंगी, तो इससे आपको अनगिनत फायदे मिल सकते हैं। इसे खाने का सही तरीका और इसके फायदों के बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानते हैं।

बारिश के मौसम में शहद खाने के फायदे

- शहद का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और कई बीमारियों से बचाव होता है।
- इससे सर्दी-खांसी और जुकाम से बचाव में भी मदद मिलती है।
- शहद में प्रीबायोटिक गुण होते हैं। रोजाना 1 चम्मच शहद खाने से मानसून में होने वाली पाचन संबंधी दिक्कतों में आराम मिलता है।
- अगर आप वजन कम करना चाहती हैं, तो भी शहद का सेवन फायदेमंद रहता है।
- शहद में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह मौसमी बीमारियों और इंफेक्शन्स को दूर करता है।
- रोजाना 1 चम्मच शहद खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर को ताकत मिलती है।

शहद खाने का सही तरीका

- शहद को आप मानसून में कई तरीकों से डाइट में शामिल कर सकती हैं।
- वजन कम करने के लिए 1 चम्मच शहद को पानी में मिलाकर खाएं।
- खांसी को दूर करने के लिए रात को 1 चम्मच शहद काली मिर्च के साथ खाएं।
- मानसून में 1 चम्मच शहद में सोंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर मिलाकर खाना भी फायदेमंद रहता है।

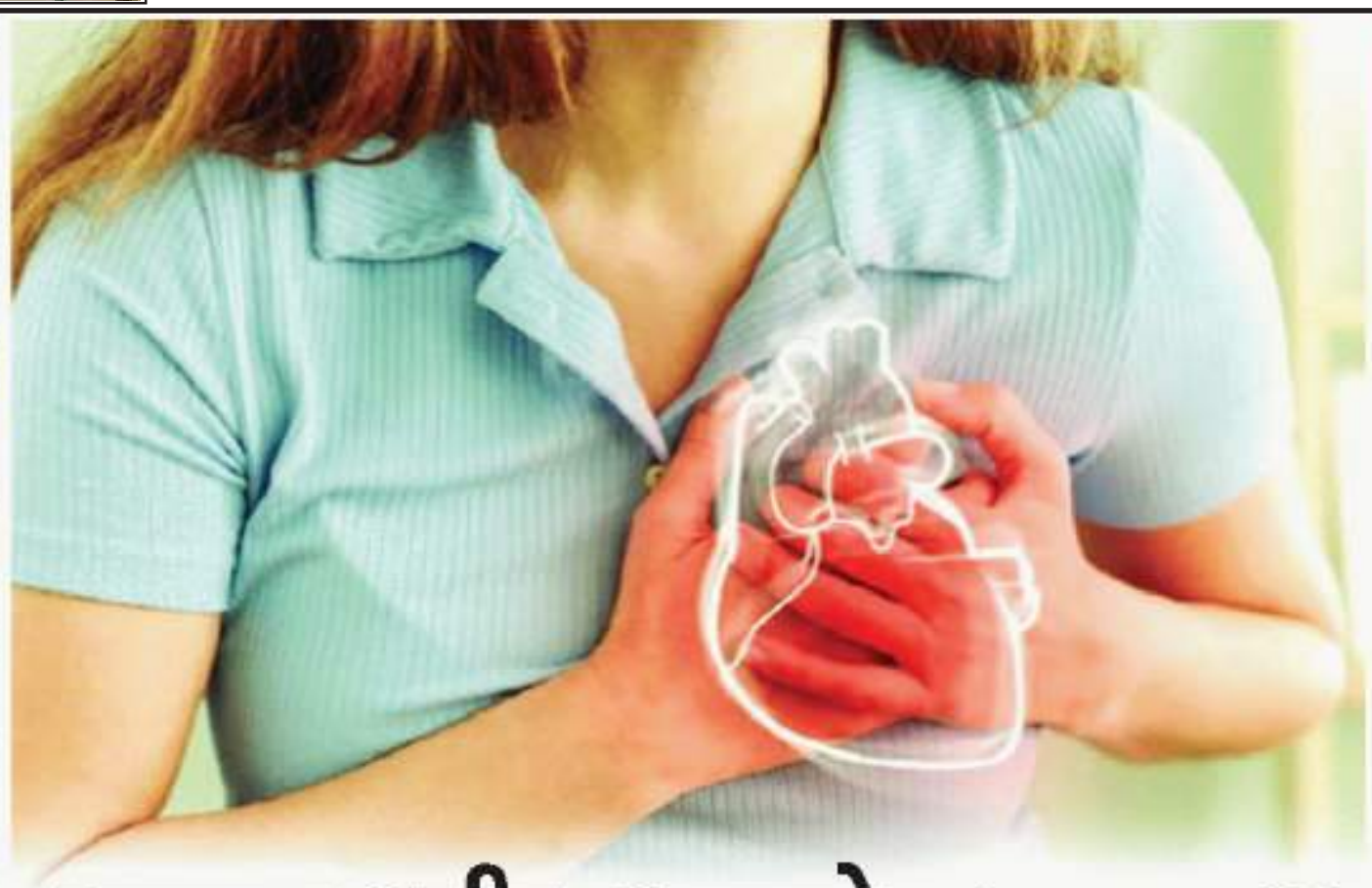

आपका शरीर आपको देता है दिल की बीमारी का संकेत

दिल की बीमारी शुरू होने से पहले शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। एक्सपर्ट से जानें वो कौन से हैं और आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं।

हमारा शरीर किसी भी तरह की बीमारी के शुरू होने से पहले हमें कुछ संकेत देता है जो ये बताते हैं कि कहीं कोई बीमारी तो शुरू नहीं हो रही है। दरअसल, कई बार हम गंभीर लक्षणों को भी नजरअंदाज कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये लक्षण आम हैं। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के बहुत जरूरी अंग जैसे दिल, किडनी, लिवर आदि हमें बीमारी से पहले कुछ न कुछ संकेत जरूर देते हैं। कुछ समय पहले हमने आपको दिल की बीमारी के संकेतों के बारे में बताया था और अब हम आपको दिल की बीमारी के कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं।

इनडायजेशन या पेट का दर्द

कई बार अचानक इनडायजेशन या पेट का दर्द शुरू होता है और ये लगातार बना रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी-किसी दिन एक-दो बार आपका पेट खराब रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि लगातार कई दिनों तक ये समस्या बनी रहे जबकि आपकी डाइट आदि में कोई बदलाव न आया हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लें। महिलाओं में ये समस्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। ये लक्षण उन्हें पहले दिखता है।

बार-बार चक्कर आना

आपको ऐसा अगर बार-बार लग रहा है कि आपको चक्कर आ रहा है। माइंड कंट्रोल नहीं है और बार-बार ये लगे कि आप बस अब बेहोश हो जाएंगे तो ये चिंता का विषय है और दिल की बीमारी का एक लक्षण भी। कुछ मामलों में ये नर्वस सिस्टम की खराबी या बैकबोन या ब्रेन क्लॉटिंग को भी दर्शाता है, लेकिन अगर दिल की बीमारी शुरू होने वाली है तो उसका एक लक्षण ये हो सकता है। चाहें कोई भी कारण हो ये बिलकुल सही नहीं होता और इसे इग्नोर करना सेहत के साथ खेलने जैसा है। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

बहुत ज्यादा थकान बनी रहना

अगला लक्षण थकान का होता है। थकान ऐसी नहीं कि बहुत काम कर लिया तो थक गए बल्कि थकान ऐसी की आप ये भी न समझ पाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दिन भर का काम करना भी मुश्किल रहे और जरा सा उठने-बैठने पर आप हांफने लगें। ऐसे में आपका दिल आपको इशारा कर रहा है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और डॉक्टर से संपर्क करें।

अचानक खर्राटे लेकर सोना

कई बार लोगों को साइनस की वजह से या फिर नाक के आकार की वजह से खर्राटे आते हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई समस्या नहीं है और अचानक खर्राटे शुरू हो गए हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

पैर, एड़ियों और तलवों का सूझ जाना

पैरों में लगातार सूजन का बना रहना किडनी और दिल दोनों की बीमारी का संकेत माना जा सकता है। जब हमारा दिल अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो इन अंगों तक सही तरह से खून भी नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में सूजा-सूजा महसूस होता है और आपके पैरों के तलवों और एड़ियों, पैरों और तलवों पर ब्लोटिंग होने लगती है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि पैरों में लगातार सूजन बनी हुई है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

दिल की धड़कन और पल्स रेट का बढ़ना और गिरना

आपके दिल की धड़कन आपको ये बता सकती है कि दिल की बीमारी शुरू हो रही है या नहीं। पल्स रेट का अचानक बढ़ना, गिरना ये भी इस बात का अंदेशा दे सकता है। आपको अचानक घबराहट होना और दिल का तेजी से धड़कना। अगर किसी चीज़ से डर गए हैं, बहुत ज्यादा दौड़ लिए हों, बहुत एक्साइटेड हों तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आप सामान्यत- जैसे बैठते हैं वैसे बैठे हैं और अचानक घबराहट, पसीना और दिल की धड़कन का असामान्य हो जाना दिखता है तो ये लक्षण सही नहीं है।

कुछ अन्य लक्षण

- इनके अलावा दिल की बीमारी के कुछ अन्य लक्षण भी दिखते हैं जैसे-
- सीने में दर्द
- बार-बार सांस फूलना
- बार-बार हाथ या पैर का सुन्न हो जाना या ठीक हो जाना
- लेफ्ट आर्म में दर्द और उसका सुन्न होना
- अपर एब्डोमिन या बैक में दर्द होना
- ऐसा कोई भी असामान्य लक्षण अगर आपको दिख रहा है तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने में देरी न करें। ध्यान रखें कि कभी-कभी कुछ खाने-पीने, दौड़ने-भागने, डरने या फिर बीपी के ऊपर-नीचे होने की वजह से भी ऐसे लक्षण होते हैं, लेकिन आपको अगर ऐसे लक्षण लगातार बने हुए हैं तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

बरसात के मौसम में चिकनगुनिया का जोखिम भी बढ़ जाता है। यह मच्छरों से होने वाली बीमारी है। आइए जानते हैं इसके लक्षण

बरसात में बढ़ जाता है चिकनगुनिया का जोखिम

बरसात के मौसम में वायरल संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। डेंगू, मलेरिया के साथ ही चिकनगुनिया का भी जोखिम बढ़ जाता है। यह बीमारी चिकनगुनिया वायरस मच्छर के कारण होती है। इंफेक्टेड मादा मच्छर एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस के काटने से कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है। यह बीमारी आमतौर पर अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, भारत के देशों के लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है। आपको बता दें कि यह संक्रमण पहली बार 1952 में पूर्वी अफ्रीका में देखा गया था। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 7 दिनों के बाद इसके लक्षण नजर आने लगते हैं जो की खुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं लेकिन बच्चे , बुजुर्ग या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में यह गंभीर रूप ले सकता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए होता है। आइए नजर डालते हैं इसके लक्षणों पर

चिकनगुनिया के लक्षण

- सिर दर्द
- जोड़ों में दर्द
- थकान
- चक्कर आना
- लिम्फ नोड्स में संवेदनशीलता
- उल्टी
- मांसपेशियों में दर्द
- चेहरे पर चकते

क्या है इसका इलाज

एक्सपर्ट बताते हैं की इस मच्छर जनित बीमारी का पता लगाने के लिए साधारण सा ब्लड टेस्ट किया जाता है। बता दें कि चिकनगुनिया से बचाव के लिए किसी भी तरह की वैक्सीन और इलाज नहीं है। आराम, तरल पदार्थ और ओवर द काउंटर दर्द और बुखार की दवाओं से इसके लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है।

बरसात में क्यों बढ़ जाता है जोड़ों का दर्द?

बारिश का मौसम सुहावना जरूर होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सुकून भरा हो, कुछ लोग ऐसे भी है जिनके लिए यह मौसम आफत बन जाता है। इस मौसम में खूब सारी समस्या होने लगती है। अक्सर जॉइंट पेन की शिकायत बढ़ जाती है। आइए जानते है कि आखिर बारिश के मौसम में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? और यह समस्या किन लोगों को परेशान करती है। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की।

बरसात में क्यों बढ़ जाता है जोड़ों का दर्द?

एक्सपर्ट बताते हैं कि मानसून के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। वातावरण में नमी का स्तर बढ़ जाता है इससे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, खासकर समस्या उन लोगों होती है जिनकी हड्डिया कमजोर होती है। मौसम में ठंडापन होने के कारण लोग पानी का सेवन कम कर देते हैं,इससे फ्लूड की कमी हो जाती है। इसके कारण भी जोड़ों का दर्द बढ़ने लगता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि वायुमंडल में पाए जाने वाले एयर प्रेशर को बैरोमेट्रिक दबाव कहा जाता है, मानसून में यह दबाव कम हो जाता है,तो शरीर के टिशू और मांसपेशियों में सूजन और दर्द बढ़ जाता है। कम तापमान के कारण टिशू ,मांसपेशियों जोड़ों में दर्द और ऐंठन हो सकता है। जिन लोगों को पहले कभी चोट लगी हो या गठिया की समस्या है उन्हें दर्द झेलना पड़ सकता है। इस दर्द से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है की आप इस मौसम में शारीरिक गतिविधि करते रहें और शरीर को हाइड्रेट रखें।

सोते या आराम करते समय घटाएं वजन, ये टिप्स आएंगे काम

आपने शायद इसके बारे में सुना हो कि नींद लोगों के लिए कितनी जरूरी होती है। नींद न सिर्फ हमारे थके हुए शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए जरूरी है बल्कि इसके कारण हमारे शरीर के कई फंक्शन्स पूरे होते हैं। उदाहरण के तौर पर शरीर के सभी मसल्स रिपेयर होते हैं, स्किन केयर के लिए ये समय सही होता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इस समय सही से काम करता है। ऐसे में आपका शरीर नींद में भी वजन लूज कर सकता है पर उसके लिए आपको अपने शरीर को तैयार करना होगा।

स्लीप साइकल पर ध्यान देना जरूरी है

ज्योति जी के मुताबिक ये कई लोगों के साथ होता है कि उन्हें क्वालिटी की जगह क्वांटिटी की चिंता होती है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी दिन 12-13 घंटे सोने के बाद अगले दिन आप बहुत थका हुआ फील करते हैं, लेकिन वहीं 6-7 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपके लिए अच्छी साबित होती है। नींद में हमारे शरीर में कई तरह की गतिविधियां होती हैं और शरीर का मेटाबॉलिज्म और सभी तरह की रिपेयर प्रक्रिया सही से काम करे इसके लिए आपको क्वालिटी स्लीप लेनी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वांटिटी स्लीप के मुकाबले हमेशा क्वालिटी स्लीप अच्छी होती है। ऐसा लाइफस्टाइल के कारण होता है। एक अच्छी स्लीप साइकल ही आपके वेट लॉस को प्रमोट करेगी।

हेल्दी डाइट और डिनर का टाइम

वेट लॉस के लिए पहले आपको अपने शरीर को तैयार करना होगा। इसके लिए दिन भर में हेल्दी डाइट जरूरी है। एक तरह से देखा जाए तो यहां भी क्वालिटी और क्वांटिटी वाला फंडा आता है। ये जरूरी नहीं कि आप हेल्दी डाइट लेने के लिए बिलकुल कम खाएं या फिर एक समय पोहा-स्प्राउट्स आदि खाने के बाद दूसरे समय छोले-टिक्की, पकोड़े, बर्गर आदि खा लें। आप चीट डाइट ले सकते हैं, लेकिन वो कभी-कभी होना चाहिए। साथ ही नींद में आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे उसके लिए आपको रात में सोने से करीब 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना होगा। ऐसा करने से आपके खाने को डायजेस्ट होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। सोने से जस्ट पहले अगर आप खाते हैं तो शरीर अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ खाने को डायजेस्ट करने में ही लगा देगा। ये नींद में आपके मसल रिपेयर या वेट लॉस के काम पर असर नहीं करेगा।

सोने से पहले सारे गैजेट्स को बंद कर दें

ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा पर धीरे-धीरे सब ठीक होने लगेगा। ये टिप बहुत जरूरी है अगर आप क्वालिटी नींद चाहते हैं तो। फोन और गैजेट्स के कारण हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है और इसलिए ये सही नहीं होता कि हम अपनी नींद में इनकी वजह से खलल डालें। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि कितनी अच्छी तरह से आपको नींद आ रही है। हां, ये जरूर है कि शुरुआत में आपको इससे थोड़ी दिक्कत होगी और बार-बार मन करेगा कि आप अपना फोन या लैपटॉप देख लें पर ऐसा नहीं करना ठीक है।

रात में प्रोटीन बहुत जरूरी है

अच्छी नींद और रात में भूख न लगे, बार-बार नींद न टूटे, खाना सही डायजेस्ट हो और साथ ही साथ शरीर अपने रेगुलर काम जैसे सेल रिपेयर आदि ठीक से करे। वैसे तो आप रात में प्रोटीन शेक भी पी सकते हैं, लेकिन हल्दी वाला दूध, थोड़े से नट्स आदि इस काम को बखूबी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले ये लें ताकि आपको बार-बार मिडनाइट हंगर की समस्या न हो। जब आप सोते हैं तो आपकी सारी मसल्स रिकवर होती हैं और इस काम में प्रोटीन आपकी मदद करता है।

मेडिटेशन करेगा मदद

आप स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन आदि सोने से पहले कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपकी नींद को बेहतर करेगा बल्कि इसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी सही होगा। आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग आदि कुछ भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। दिमाग की शांति के लिए भी ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है।

कलिंग समाचार

संपादकीय

सोमवार 01 दिसंबर 2025

ताजमहल के साथ देश की दीवारों में रिसता पानी

बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष जवाब चाह रहा है। अमेरिका की तरफसे लगातार भारत का अपमानए दक्षिण भारत में हिंदी थोपने की कोशिश का आरोप और त्रिभाषा फार्मूलाए परिसीमन में दक्षिण की सीटें घटाने की कोशिशए किसान आंदोलन और एमएसपी का वादाए मतदाता सूची में गड़बड़ी और मतदाता फोटो पहचान पत्र के अंकों में हो रहा दोहरावए वक्फ संशोधन विधेयक में विपक्ष की आपत्तियों को नजरंदाज करनाए मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश के बीच फिर से हिंसाए ऐसे अनेक मुद्दे हैं दिन पर सरकार को विपक्ष की बात और सवाल सुनकर यथासंभव जवाब देना चाहिए। इन तमाम सवालों के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल एआईएमआईएम के सांसद असद्दुदीन ओवैसी ने कियाए जिस पर सरकार का जवाब चिंताजनक है। ओवैसी साहब ने सवाल किया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को श्डिटाक्सिफाईश् यानी विषमुक्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि एएसआई संविधान के धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के सिद्धांत के साथ काम करेघ् दरअसल असद्दुदीन ओवैसी ने आरोप लगाया था कि पिछले 50 साल से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ;एएसआईद्ध हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। और फिर उन्होंने इस संस्था के संविधान के मुताबिक काम करने पर सवाल कियाए साथ ही कहा कि यह सरकार पिछले 11 वर्षों से सत्ता में है। संस्कृति मंत्रालय में 6516 पद रिक्त हैंए संरक्षण शाखा में 67 से अधिक पद रिक्त हैंए पुरातत्व और पुरालेखशास्त्र के प्रमुख प्रभागों में एक महत्वपूर्ण कमी हैए मंत्रालय कैसे सुनिश्चित करता है कि केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों का रखरखाव और संरक्षण कैसे किया जाता है? एआईएमआईएम सांसद के इस सवाल पर केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि 50 साल के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकताए लेकिन पिछले 10 साल आठ महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार श्सबका साथए सबका विकासए सबका विश्वास और सबका प्रयासश् की विचारधारा के साथ साथ काम कर रही है। वहीं उन्होंने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि देश में मोदी सरकार से पहले चंद लोगों को श्पूजा पद्धति या वोट बैंक की ताकत के आधार परश् कुछ विशेषाधिकार मिलते थे जो समानता की श्रेणी में आने के बाद समाप्त हो गए हैं। मंत्री महोदय का इशारा किन लोगों की तरफ थाए यह समझना कठिन नहीं है। लेकिन दुख होता है यह देखकर कि जिस मंत्रालय पर भारत की संस्कृति और विरासत यानी गंगा.जमुनी तहजीब को संभालने और आगे बढ़ाने के साथ ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा की खास जि मेदारी हैए वहां सही सवाल पर चुनावी नारेनुमा जवाब दिए जा रहे हैं। बता दें कि गजेन्द्र सिंह शेखावत ने असद्दुदीन ओवैसी के सवाल के जवाब में यह स्वीकार किया है कि जहां तक ताजमहल के रखरखाव का विषय है तो यह बात सही है कि पानी के रिसाव की एक घटना सामने आई थी। लगातार बारिश के कारण जो स्थिति बनीए उसमें तुरंत सुधार किया गया है। केंद्र सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। पाठक जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक है और विदेशों से बड़ी सं या में सैलानी इस अद्भुत कलाकृति को देखने आते हैं। उत्तरप्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों को ताजमहल के कारण अच्छा.खासा राजस्व प्राप्त होता है। फिर भी इस ऐतिहासिक इमारत में बारिश का पानी चूने लगेए तो समझा जा सकता है कि इसके रखरखाव में कैसी लापरवाही बरती जा रही है। वैसे भी तेल शोधन संयंत्रों के कारण ताजमहल की मौलिक खूबसूरती काफी हद तक नष्ट हो गई है। उधर हिंदुत्व के उन्मादी लोगों के कारण भी ताजमहल को काफी खतरा हो गया है। दक्षिणपंथी इसे तेजोमहालय कहते हैं और पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू महासभा से जुड़े दो युवकों ने ताजमहल के भीतर कब्र पर गंगाजल भी डाल दिया थाए जिसके बाद उन्हें गिर तार किया गया।

निवेशकों को लुभाने के लिए ममता बेताब, चुनाव से पहले फिर ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस

रवींद्र नाथ सिन्हा

पश्चिम बंगाल में अप्रैल.मई 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं.जो लगभग 14 महीने दूर हैं। कुछ सप्ताह पहले तक यह माना जा रहा था कि बीजीबीएस का आठवां संस्करण उनके तीसरे कार्यकाल का आखिरी होगा। लेकिनए दूसरे और अंतिम दिन अधिकारियों को अगले बीजीबीएस की तैयारी अभी से शुरू करने की उनकी सलाह से यह संकेत मिलता है।

5 और 6 फरवरी को यहां आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस शिखर स मेलन ;बीजीबीएसद्ध के दो दिवसीय आठवें संस्करण ने मु यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की बेताबी को उजागर किया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों और आम धारणा को खारिज करने की कोशिश की कि 2011 में शुरू हुए उनके शासन के दौरान औद्योगीकरण में कमी आयी हैए जिनका आशय है कि भारी इंजीनियरिंग इकाइयोंए एकीकृत इस्पात संयंत्रोंए रसायनों और पेट्रो.रसायन परिसरों जैसे विनिर्माण उपक्रमों आदि में रोजगार पैदा करने वाले निवेशों की अनुपस्थिति। यह इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार ने 2015 से बीजीबीएस के सात संस्करण आयोजित किये हैं और दावा किया है कि राज्य को बड़ी सं या में निवेश प्रस्ताव मिले हैंए जिनकी कुल राशि 19 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। लेकिनए राज्य ने शायद ही कभी शुरू की गयी परियोजनाओं और कार्यान्वयन के अधीन और कमीशनिंग तिथियोंध्अनुसूची का विवरण साझा किया हो। सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि बड़ी सं या में शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में राज्य छोड़ रहे हैं। अकुशल और अर्ध.कुशल श्रमिकों का बड़े पैमाने पर बाहर जाना एक कठोर वास्तविकता है। पिछले दो.तीन वर्षों मेंए केंद्र के साथ टकराव और मानदंडों का पालन करने में विफलता और केंद्रीय निधियों के उपयोग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण राज्य को भारी कीमत चुकानी पड़ी हैए क्योंकि नई दिल्ली ने ग्रामीण रोजगार सृजन और ग्रामीण आवास कार्यक्रम निधियों को जारी करने पर रोक लगा दी है।वैकल्पिक राज्य.वित्त पोषित योजनाओं के साथ परिणामी असंतोष को कम करने की ममता की कोशिश उस चीज़ का विकल्प नहीं है जो राज्य केंद्रीय निधियों के नियमित प्रवाह के साथ हासिल कर सकता है। इस पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि मु यमंत्री ने बीजीबीएस के आठवें संस्करण को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है। उद्योगपतियों को अपने राज्य में रोजगार सृजन करने वाले निवेश के लिए राजी करने के उनके प्रयासों को व्यापक प्रचार अभियान के माध्यम से दर्शाया गया है।

पश्चिम बंगाल में अप्रैल.मई 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं.जो लगभग 14 महीने दूर हैं। कुछ सप्ताह पहले तक यह माना जा रहा था कि बीजीबीएस का आठवां संस्करण उनके तीसरे कार्यकाल का आखिरी होगा। लेकिनए दूसरे और अंतिम दिन अधिकारियों को अगले बीजीबीएस की तैयारी अभी से शुरू करने की उनकी सलाह से यह संकेत मिलता है कि वह अगला व्यावसायिक स मेलन . नौवां संस्करण . फरवरी 2026 मेंए यानी अगले विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित करने की इच्छुक हैं। ऐसा लगता है कि वह 2026 में इस दावे के साथ मतदाताओं का सामना करना चाहेंगी कि उन्होंने निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने और राज्य के औद्योगीकरण के लिए ईमानदार प्रयास किये हैंए तथा विपक्ष का आरोप राजनीति से प्रेरित है।

इसका कारण 2006 के विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चे की सत्ता में वापसी के तुरंत बाद सिंगूर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ तत्कालीन विपक्षी नेता ममता बनर्जी का निरंतर आंदोलन था। यह उल्लेखनीय है कि सिंगूर में बड़े झटके के बावजूद बॉ बे हाउस ने पश्चिम बंगाल में निवेश कभी नहीं रोका। वास्तव मेंए उन्होंने राज्य के होटलों में अपनी उपस्थिति को काफी मजबूत किया है। टाटा समूह ने टाटा स्टील क्षेत्र में निवेश किया है और खड़गपुर में लौह धातु और इंजीनियरिंग सुविधाओं में नये निवेश किये हैं।

बीजीबीएस.8 के दौरान ममता ने दो कार्य किये जो उनकी चिंताओं और गंभीरता को दर्शाते हैं। सबसे पहलेए उन्होंने बीरभूम जिले में लंबे समय से चर्चित देवचा.पचमी कोयला परियोजना पर सुबह से भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर नये आंदोलन से निपटने के बाद 6 फरवरी को काम शुरू करवाया। यहां काम का मतलब प्राथमिक रूप से ओवर.बर्डन को हटाना है. इस मामले मेंए बेसाल्ट और ब्लैकस्टोन। यह एक लंबी खींची हुई कवायद होने जा रही है क्योंकि ओवर.बर्डन की मात्रा बहुत अधिक है और इसलिएए चयनित खदान विकास ऑपरेटर द्वारा कोयले का वास्तविक उठाव 12.18 महीनों के बाद ही संभव हो सकता है। लेकिनए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उदार मुआवजा पैकेज और समयबद्ध पुनर्वास कार्यक्रम ने प्रशासन को देवचा.पचमी कोयला भंडार निकालने की योजना तैयार होने के एक दशक बादए शायदए वास्तविक खनन.संबंधी गतिविधि शुरू करने में सक्षम बनाया है। आधुनिक खनन तकनीकों और सराहनीय मशीनीकरण के साथ इसकी रोजगार सृजन क्षमता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है।

दूसरेए 5 फरवरी कोए बीजीबीएस के पहले दिन हीए ममता ने अपने सामान्य मुखर रुख से हटकर मीडिया के सामने खुलासा किया कि उन्होंने टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से श्कार्यक्रम की पूर्व संध्या परश् ;वास्तव मेंए 4 फरवरी की रात कोद्ध फोन पर बातचीत की है। चंद्रशेखरन निवेश प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए जल्द ही शहर का दौरा करेंगे और उन्होंने श्कोलकाता से यूरोप के किसी गंतव्य के लिए सीधी उड़ान शुरू करने के मेरे अनुरोध पर उचित ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि व्यस्तता के कारण वे स मेलन में उपस्थित नहीं हो सके।

यह ध्यान देने वाली बात है कि ममता ने रतन टाटा के निधन ;9 अक्टूबरए 2024द्ध के चार महीने बाद और तत्कालीन बॉ बे हाउस के सुप्रीमो रतन टाटा द्वारा सिंगुर छोटी कार उद्यम से हाथ खींचने ;3 अक्टूबरए 2008द्ध के 16 साल बाद टाटा संस के प्रमुख से सीधे संपर्क स्थापित करने का फैसला कियाए जबकि उस समय यह लगभग 85 प्रतिशत पूरा हो चुका था। इसका कारण 2006 के विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चे की सत्ता में वापसी के तुरंत बाद सिंगूर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ तत्कालीन विपक्षी नेता ममता बनर्जी का निरंतर आंदोलन था। यह उल्लेखनीय है कि सिंगूर में बड़े झटके के बावजूद बॉ बे हाउस ने पश्चिम बंगाल में निवेश कभी नहीं रोका। वास्तव मेंए उन्होंने राज्य के होटलों में अपनी उपस्थिति को काफी मजबूत किया है। टाटा समूह ने टाटा स्टील क्षेत्र में निवेश किया है और खड़गपुर में लौह धातु और इंजीनियरिंग सुविधाओं में नये निवेश किये हैं। उनके अधिकारियों ने बीजीबीएस सत्रों में भाग लिया है। लेकिनए मौजूदा टाटा संस प्रमुख के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने की मु यमंत्री की नयी पहल राज्य के लिए शुभ संकेत है।राज्य की अर्थव्यवस्था और देश के तेल और गैस परिदृश्य के लिए मु य महत्व की बात यह है कि मु यमंत्री ने घोषणा की है कि ओएनजीसी को जल्द ही 24 परगना उत्तर जिले के अशोकनगर में अपनी परियोजना के लिए अपेक्षित पेट्रोलियम खनन पट्टा दिया जायेगाए जहां पीएसयू दिग्गज तेल और गैस की खोज करने में सफल रहा है और जिसके लिए राज्य ने कंपनी को एक रुपये में 1ए500 एकड़ जमीन दी है। खनन पट्टा वाणिज्यिक उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्राप्त प्रस्तावों में सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू समूह की सुपर थर्मल ;800 मेगावाट – 2द्ध बिजली परियोजनाए अंडाल हवाई अड्डे में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी में समूह की रुचिए मुकेश अंबानी समूह द्वारा खुदराए दूरसंचार और डेटा सेंटर में नये निवेशए अंबुजा समूह द्वारा रियल एस्टेटए आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा में निवेशए आरपीजी संजीव गोयनका समूह द्वारा बिजलीए शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में निवेश और आईटीसी द्वारा आतिथ्यए आईटी और एआई में निवेश शामिल हैं। अतीत से हटकरए मु यमंत्री ने बताया कि बीजीबीएस के पिछले सात संस्करणों में निवेशकों द्वारा बतायी गयी 19 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं में से 13 लाख करोड़ रुपये की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और छह लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की शेष योजनाएं पाइपलाइन में हैं। हाल ही में संपन्न आठवें बीजीबीएस में कुल 4.41 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। पिछले एक दशक में जिन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई हैए उनमें आईटी और आईटीईएसए रियल एस्टेटए सीमेंट और आतिथ्य शामिल हैं।

ट्रंप की नीतियों से बढ़ सकता है भारत का आर्थिक संकट

डॉ. अजीत रानाडे

ट्रंप की नीतियां हमें सीधे चीनी डंपिंग खतरेए शेयर बाजारों से विदेशी निवेशकों के पलायनए कमजोर रुपये और परिणामस्वरूप तरलता की कमीए उच्च ब्याज दरों व मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के माध्यम से प्रभावित कर रही हैं। बेशकए हमारे सभी आर्थिक संकटों के लिए ट्रंप की नीतियों को दोष देना गलत है। हम राजकोषीय सीमाओं का भी सामना कर रहे है।

डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के सैंतालीसवें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने यह बड़ी चुनावी जीत हासिल की। इसके साथ ही वे एकमात्र पूर्व और पदारुढ़ अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें ऐसे अपराध में दोषी ठहराया गया है जिसमें आम तौर पर कठोर जुर्माना या जेल की सजा होती है। तो भी सजा सुनाने वाले न्यायाधीश ने होने वाले राष्ट्रपति को दंडित करने से इनकार कर दिया और उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया। उनके खिलाफ तीन अन्य आपराधिक और गुंडागर्दी के मामले भी हैं जिनमें कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है या शायद नहीं भी हो सकती है। अपराधी के रूप में दोषी ठहराए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को अब कई देशों में प्रवेश से इनकार करने का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि भारत भी दोषी ठहराए गए अपराधियों को वीजा नहीं देता है। राष्ट्रपति ट्रंप जिन देशों की यात्राएं करना चाहते हैं उन देशों के लिए यह एक संवेदनशील राजनयिक चुनौती पेश करने वाला विषय है।

ट्रंप के राष्ट्रपति पद की यह एक अभूतपूर्व शुरुआत है। उनके लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी होने के बावजूद लोगों ने उन्हें बहुत निर्णायक रूप से वोट दिया है। ट्र प ने जिन नीतियों की घोषणा की है तथा जिन्हें वे लागू करने की योजना बना रहे हैंए वे योजनाएं और भी लोकप्रिय हैं। उनके चुनावी समर्थन की तुलना में उनकी नीतियों को दस प्रतिशत अधिक अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। वे नीतियां क्या हैंघ् इनमें अवैध विदेशियों के खिलाफ कड़े कदमए एच1बी वीजा पर आने वाले वैध विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित करनाए विशेष रूप से मैक्सिकोए कनाडा और चीन से आने वाले सामानों पर उच्च आयात शुल्क लगाना शामिल है। उनके समर्थक व अन्य लोग भी इस बयानबाजी पर विश्वास करने लगे हैं कि विदेशी उत्पादक अमेरिकी उपभोक्ता बाजार का श्दोहनश् करते हैं और अमेरिकी नौकरियों की चोरी करते हैं। इसलिए ट्र प के नए कार्यकाल में अब विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को अमेरिकी उपभोक्ता तक मु त पहुंच उपलब्ध नहीं होने दी जा रही है। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 2016 से 2020 तक उन्होंने अमेरिका में आयात किए जा रहे लगभग एक लाख करोड़ डॉलर के सामान पर उच्च टैरिफ लगाया था। वह टैरिफ अब और भी ज्यादा होगा। अमेरिकी आयकर विभाग की श्आंतरिक राजस्व सेवाश् का अनुकरण करते हुए उन्होंने श्बाहरी राजस्व सेवाश् स्थापित करने की घोषणा की है। ट्र प अपने मतदाताओं से कहते हैं कि अपनी जेब काटने के बजाय मैं उन गंदे विदेशियों की जेबें काटने जा रहा हूं जो मुक्त बाजार पहुंच का अनुचित लाभ उठाते हैं।

ट्र प 2ण्0 की नीतियों का भारत पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। सबसे पहलेए अमेरिका में आने वाले चीनी सामानों पर उच्च शुल्कए जिसके कारण चीन उन उत्पादों को तीसरे देशों में भेज देगा। चीन मंदी और क्षमता से अधिक उत्पादन का सामना कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि चीनी बहुत कम कीमत पर अन्य देशों में माल डंप करने की कोशिश करेगा जिनमें विशेष रूप से स्टीलए अलौह धातुओंए उपभोक्ताए इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायनों जैसी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। पहले से ही चीन के साथ भारत का 100 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार घाटा है जिसे कम करना मुश्किल साबित हो रहा है।दूसरा प्रभाव सस्ता रूसी कच्चे तेल खरीदने के खिलाफप्रतिबंधों के माध्यम से है। भारत को सस्ते कच्चे तेल की खरीद और अमेरिका व यूरोप को परिष्कृत पेट्रोल और डीजल निर्यात करने से फायदा हुआ। इसकी बारीकी से जांच होने की उ मीद है तथा मामला और अधिक बिगड़ जाएगा। तीसरा प्रभाव मजबूत डॉलर के माध्यम से होता है जिसका अर्थ है रुपये का और कमजोर होते जाना। यह विदेशी निवेशकों को परेशान करता है और यह बड़े पैमाने पर पूंजी के बाहर जाने के रूप में परिलक्षित हुआ है। इस वर्ष जनवरी में यानी 17 जनवरी तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ;एफआईआईद्ध ने 47ए000 करोड़ यानी करीब 6 अरब डॉलर की निकासी की है और शेयर बाजार को बड़ी टक्कर मिली है।इस जनवरी में हुई यह निकासी 2008 के बाद से सबसे अधिक है। डॉलर की निकासी से रुपया गिरकर 87 पर आ गया है। इसमें और गिरावट आ सकती है। रुपये की मजबूती को बचाने की कोशिश में भारतीय रिजर्व बैंक डॉलर बेचता है। जैसे ही एफआईआई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हैए डॉलर की कमी उभरकर सामने आती है जिससे रुपया कमजोर और डॉलर मजबूत हो जाता है। रुपये को और कमजोर होने से बचाने के लिए आरबीआई अपने कीमती विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है। एक अनुमान के अनुसार सितंबरए 2024 के अंत से आरबीआई ने समस्या के समाधान के लिए लगभग 40 अरब डॉलर बेचे होंगे। यह भारत के विदेशी मुद्रा के स्टॉक को कम करता है व बैंकिंग प्रणाली में तरलता को भी कम करता है। इसका शुद्ध परिणाम यह भी है कि रुपया अभी भी गिर रहा है तथा बैंकों को तरलता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबरए 2024 के अंत तक आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध तरलता घाटे की रिपोर्ट कर रहा है। यह तरलता संकट अल्पकालिक ब्याज दरों को तेजी से बढ़ाता है।यह अच्छी खबर नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ आरबीआई पॉलिसी रेट ;शॉर्ट टर्म रेपो रेटद्ध को नीचे लाने की मांग की जा रही है। भारत सरकार के साथ.साथ आवासए रियल एस्टेट और व्यक्तिगत वित्त जैसे ब्याज संवेदनशील क्षेत्रों से कम ब्याज दरों की मांग आ रही है। इस तरह परिवारों की वास्तविक खर्च करने योग्य आय बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही हैए जिसका श्रेय मुद्रास्फीति को देना होगा जो घरेलू बजट को खा रही है।

वेतन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए उपभोक्ता खर्च वृद्धि में खामोशी दिखाई दे रही है जिससे जीडीपी वृद्धि के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं। इस तरह इस साल जीडीपी वृद्धि दर पिछले साल के 8.2 प्रतिशत की तुलना में कम यानी 6.4 फीसदी है। अगले वर्ष भी विकास दर लगभग 6.5 प्रश रह सकती है

इस प्रकार ट्र प की नीतियां हमें सीधे चीनी डंपिंग खतरेए शेयर बाजारों से विदेशी निवेशकों के पलायनए कमजोर रुपये और परिणामस्वरूप तरलता की कमीए उच्च ब्याज दरों व मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के माध्यम से प्रभावित कर रही हैं। बेशकए हमारे सभी आर्थिक संकटों के लिए ट्र प की नीतियों को दोष देना गलत है। हम राजकोषीय सीमाओं का भी सामना कर रहे हैं लेकिन केवल सरकारी खर्च से विकास को बढ़ावा देने से काम नहीं चलेगा। निजी निवेश खर्च में भी तेजी आनी होगी। यह उपभोक्ता विश्वास और मांग के बढ़ने पर निर्भर करता है जो रोजगार तथा मजदूरी वृद्धि पर निर्भर करता है। यह सब आपस में जुड़ा हुआ है। इस सबमें मनोविज्ञान एवं भावना को एक बड़ी भूमिका निभानी है।

दुनिया में इस बारे में अनिश्चितता है कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रपति ट्र प कितने विघटनकारी होंगे। अगर वे यूक्रेन में संघर्षविराम के लिए जोर देते हैं तो यह एक प्लस पॉइंट होगाए लेकिन अगर अमेरिका हठवादी रवैये पर कायम रहता है तथा अधिक संरक्षणवादीए अलगाववादी और व्यापारवादी बन जाता है तो यह मुक्त व्यापार के लिए अच्छी खबर नहीं है।

विविध समाचार

ट्रैवल एजेंट के खिलाफ शिकायत पर कथित निष्क्रियता के बाद युवक ने आत्महत्या की

फगवाड़ा ३०/११ (संवाददाता): पंजाब में सुल्तानपुर लोधी के पास कर्मजीतपुर गाँव के एक युवक ने रविवार को एक ट्रैवल एजेंट के खिलाफ पुलिस में दर्ज शिकायत पर कथित तौर पर कोई कार्रवाई न होने पर आत्महत्या कर ली। एजेंट ने उसे विदेश भेजने का वादा करके उससे 25 लाख रुपये लिए थे। इस मामले ने पुलिस विभाग में गंभीर चिंता पैदा कर दी है क्योंकि मृतक ने एक सुसाइड नोट में ट्रैवल एजेंट और एक डीएसपी दोनों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

जानकारी के अनुसार, कर्मजीतपुर निवासी गुरप्रीत सिंह ने दो साल पहले विदेश यात्रा की व्यवस्था के लिए डडविंडी गाँव के एक ट्रैवल एजेंट को 25 लाख रुपये दिए थे। हालाँकि, लंबे इंतजार के बाद भी एजेंट ने न तो उसे विदेश भेजा और न ही पैसे वापस किए। देरी और धोखाधड़ी के संदेह से परेशान होकर, गुरप्रीत ने दो महीने पहले कपूरथला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत दी थी। बाद में यह मामला डीएसपी (एनडीपीएस) सुखपाल सिंह रंधावा को सौंप दिया गया। शिकायत को जाँच के लिए भेजे जाने के बावजूद, गुरप्रीत और उसके परिवार ने आरोप लगाया कि कोई प्रगति नहीं हुई। उसके पिता बूटा सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय की माँग करते हुए कई बार पुलिस के विभिन्न कार्यालयों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लंबे समय तक देरी और समाधान न होने से गुरप्रीत कथित तौर पर बेहद निराश हो गया। गुरप्रीत ने घर पर ही जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत तेजी से बिगड़ी और उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत और बिगड़ने पर उसे जालंधर के एक अन्य निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद, शोकाकुल परिवार रविवार शाम को ग्रामीणों के साथ सुल्तानपुर लोधी थाने पहुँचा। उन्होंने ट्रैवल एजेंट और पुलिस अधिकारी के खिलाफ कथित लापरवाही के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की। परिवार ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे धरना देंगे और थाने का घेराव करेंगे।हालाँकि, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि परिवार की ओर से अभी तक कोई लिखित बयान नहीं दिया गया है। इस बीच, सुसाइड नोट में आरोपी बनाए गए डीएसपी सुखपाल सिंह रंधावा ने सोमवार को कहा कि मामले की जाँच जारी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायत से संबंधित बैंक लेनदेन रिकॉर्ड पहले ही मंगवा लिए हैं और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।इस मामले ने ट्रैवल एजेंट की कथित धोखाधड़ी गतिविधियों और शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई, दोनों की जांच को तेज कर दिया है।

चंडीगढ़ विवाद : कंट्रोल की लड़ाई पर केंद्र का बड़ा स्पष्टीकरण, एमएचए ने साफ की तस्वीर, बताया सच

चंडीगढ ३०/११ (संवाददाता): चंडीगढ़ के प्रशासनिक स्टेटस को लेकर पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से भूचाल आया हुआ है। अटकलें लगाई जा रही थीं कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ के संविधानिक दर्जे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इन चर्चाओं ने पंजाब सरकार, कांग्रेस और अकाली दल को एक सुर में विरोध करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने इन तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि केंद्र सरकार 1 से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में एक ऐसा बिल ला सकती है, जिसके तहत चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 239 की जगह आर्टिकल 240 के तहत लाया जाएगा। अगर ऐसा होता, तो चंडीगढ़ पूर्ण रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता, जहाँ प्रशासनिक अधिकार सीधे राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के हाथों में चले जाते। पंजाब के नेताओं को आशंका थी कि इस बदलाव से चंडीगढ़ पर पंजाब का पारंपरिक और प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसी डर के चलते राज्य के सभी प्रमुख दलों ने इसका कड़ा विरोध जताया था। विवाद गहराता देख केंद्र सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति साफ की है। सरकार ने स्पष्ट किया कि संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ के स्टेटस को बदलने वाला कोई भी बिल लाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। जो प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है, उसका उद्देश्य केवल "केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाना" है। इस पर भी अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्र ने पंजाब और हरियाणा की चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव में चंडीगढ़ की मौजूदा शासन–प्रशासन व्यवस्था या दोनों राज्यों (पंजाब–हरियाणा) के साथ चंडीगढ़ के 'परंपरागत संबंधों' को बदलने की कोई बात शामिल नहीं है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए और सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार–विमर्श करने के बाद ही भविष्य में कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है– "इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है।" इस स्पष्टीकरण के बाद उम्मीद है कि पंजाब में इस मुद्दे पर गर्माया सियासी माहौल कुछ शांत होगा।

कांग्रेस की विचारधारा को शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाएंगे : डा. राजेश शर्मा

जालंधर ३०/११ (संवाददाता): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डा. राजेश शर्मा ने कहा कि वह कांग्रेस की विचारधारा को शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पंडित जवाहर लाल नेहरू अपने आप में एक महान संस्थान हैं और आज के समय में बच्चों को उनकी सोच और फिलॉसफी से परिचित कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से शिक्षा बोर्ड ने "द विजनरी" नामक किताब तैयार की है, जिसका विमोचन बाल दिवस पर किया गया। इस किताब के माध्यम से नेहरू जी का विजन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। डा. राजेश शर्मा ने कहा कि नेहरू जी जैसी शख्सियत के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में अपनी बात खुलकर रख पा रहे हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता और शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते उनका दायित्व है कि कांग्रेस की सोच और विचारधारा को सकारात्मक रूप से बच्चों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा–निर्देशों के अनुसार शिक्षा बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। डा. शर्मा ने बताया कि "द विजनरी" किताब को हर स्कूल के बच्चे तक पहुँचाने की योजना है, ताकि नई पीढ़ी नेहरू जी के विचारों को समझ सके।

कांग्रेस की विचारधारा को शिक्षा के माध्यम अनुच्छेद 240 को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है केंद्र सरकारः ब्रह्मपुरा

तरनतारन३०/११ (संवाददाता): शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के उपाध्यक्ष एवंम पूर्व विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ने केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाने के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि विधेयक के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम स्पष्टीकरण को पंजाब की एकता की प्रारंभिक जीत, लेकिन एक खतरे की घंटी है। श्री ब्रह्मपुरा ने केंद्र के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह स्वीकार करना कि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया हैस यह साबित करता है कि केंद्र सरकार केवल स्थिति का जायजा ले रही थी। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में उठे तीखे विरोध ने केंद्र को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने केंद्र सरकार की तकनीकी चालाकी को लेकर कहा, "केंद्र सरकार यह दावा करके जनता को गुमराह कर रही है कि चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाना सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया को 'सरल' बनाने के लिए है। मैं पंजाबियों से अपील करता हूँ कि वे जाग जाएँ! अनुच्छेद 240 सरलीकरण का नहीं, बल्कि तानाशाही का हथियार है।" उन्होंने कानूनी पहलुओं की व्याख्या करते हुए कहा, "एक बार यह अनुच्छेद लागू हो गया, तो चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद से छीन ली जाएगी और सीधे राष्ट्रपति को यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल को हस्तांतरित हो जाएगी। इससे केंद्र को बिना किसी संसदीय बहस के रातोंरात चंडीगढ़ पर कोई भी 'काला कानून' थोपने की अनुमति मिल जाएगी। हम पंजाब की राजधानी में इस 'पिछले दरवाजे से घुसपैठ' को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।" श्री ब्रह्मपुरा ने गृह मंत्रालय के इस आश्वासन की भी आलोचना की कि सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। उन्होंने इसे एक धोखा बताया। उन्होंने कहा, "चंडीगढ़ का केवल एक ही हितधारक है, और वह है पंजाब।" उन्होंने माँग की कि स्पष्टीकरण जारी करने के बजाय, केंद्र को 'संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक 2025' को लोकसभा बुलेटिन से तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल तब तक चुप नहीं बैठेगा, जब तक विधेयक लिखित रूप से रद्द नहीं हो जाता। उन्होंने पंजाब के लोगों से केंद्र के "यू–टर्न" को अपनी सामूहिक शक्ति के संकेत के रूप में देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत में अभी भी खोट है।

धर्मेंद्र : एक युग की विदाई, एक हीरो का अमरत्व

हिंदी सिनेमा ने अपने लंबे सफर में कई सितारों को जन्म दिया, पर उनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी रोशनी समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि हर पीढ़ी की आँखों में एक नई चमक लेकर जीवित रहती है। धर्मेंद्र उन्हीं दुर्लभ सितारों में से थे, जो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय समाज के भावनात्मक ताने–बाने का हिस्सा बन चुके थे। उनका जाना एक ऐसी खामोशी छोड़ गया है, जिसे शब्दों में बाँध पाना मुश्किल है। वे सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली एक छवि नहीं थेय वे एक ऐसे इंसान थे, जिनकी गर्माहट और विनम्रता ने दर्शकों को अपने परिवारों के किसी सदस्य की तरह उनसे जोड़ दिया था। धर्मेंद्र की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली से शुरू हुई यह यात्रा संघर्ष, मेहनत और सपनों की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा लड़का जब फिल्मों की दुनिया की चमक–दमक में पहुंचता है, तो आमतौर पर व्यक्ति अपनी मूल पहचान खो बैठता है, लेकिन धर्मेंद्र ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। वही सादगी, वही देसीपन, वही अपनापन उनकी हर मुस्कान में दिखाई देता था। यही कारण है कि वे सिर्फ 'स्टार' नहीं बने, वे 'दिलों का हीरो' बने। 1960 के दशक में जब उन्होंने सिनेमा के परदे पर कदम रखा, तब दर्शकों ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि यह युवक अगले कई दशकों तक हिंदी फिल्मों का सबसे प्रिय चेहरा बनने वाला है। शुरुआत भले ही धीमी रही हो, पर उनकी आँखों में मौजूद मासूमियत और व्यक्तित्व में छिपा गहरा आत्मविश्वास बहुत जल्द ही लोगों के दिलों तक पहुँच गया। उनकी शुरुआती फिल्मों ने यह दिखाया कि उनमें संवाद की सरलता, भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति और अपने किरदार के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण जैसी विशिष्ट खूबियाँ हैं। समय के साथ धर्मेंद्र ने दिखा दिया कि वे सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि हर शैली में फिट बैठने वाले अभिनेता हैं। उन्होंने अभिनय के हर रंग को जीयाकृरोमांस की कोमलता, कॉमेडी की सहजता, एक्शन की तीव्रता और भावुक दृश्यों की गहराई। ष्अनुपमाष और ष्अनपढ़ष में उनकी रोमांटिक छवि दर्शकों का दिल चुरा लेती थी, तो ष्मेरा गांव मेरा देशष और ष्शोलेष में उनका एक्शननुमा अंदाज उन्हें 'ही–मान' की उपाधि दिलाता था। यह उपाधि किसी फैशन के कारण नहीं, बल्कि उनके स्वाभाविक दृढ़ व्यक्तित्व का प्रमाण थी। "शोले" का वीरू भारतीय सिनेमा के इतिहास का वह चरित्र है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। वीरू की मस्ती, दोस्ती, बेफिक्री और दिल की गहराई ने इस किरदार को अमर बना दिया। धर्मेंद्र कोई भूमिका निभाते नहीं थे, वे उसे जीते थे। यही कारण है कि वीरू आज भी दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान ला देता है। लेकिन धर्मेंद्र का जादू सिर्फ वीरू तक सीमित नहीं था। "चुपके चुपके" में उनकी गंभीर–स्वभाव वाली कॉमेडी यह साबित करती है कि हास्य अभिनय हमेशा उछल–कूद या अतिरंजना से नहीं आताय वह शालीनता और समयबद्ध संवादों से भी पैदा हो सकता है। धर्मेंद्र इस बात का जीता–जागता उदाहरण थे। उनके अभिनय का आधार हमेशा 'सच्चाई' रहा। वे अभिनय नहीं करते थे, वे सत्य को अभिव्यक्त करते थे। यह सत्य कभी प्रेम की कोमलता के रूप में जागता था, कभी संघर्ष की तल्खघि के रूप में। आज के समय में जब अभिनय तकनीक और बाहरी सजावट पर अधिक निर्भर होता जा रहा है, धर्मेंद्र हमें याद दिलाते हैं कि अभिनय का सबसे बड़ा केंद्र 'दिल' होता है। यही वह विशेषता है, जिसने उनकी फिल्मों को समय की सीमाओं से मुक्त कर दिया। धर्मेंद्र की एक और महानता थीकृउनकी जमीन से जुड़ाव। उन्होंने कभी खुद को महान या बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की। सैकड़ों फिल्मों की सफलता, लाखों प्रशंसक और दशकों की लोकप्रियता के बाद भी वे एक साधारण ग्रामीण की तरह बात करते थे। उनकी विनम्रता किसी बनावटी विनम्रता का परिणाम नहीं थीय वह उनके स्वभाव का हिस्सा थी। यही कारण है कि वे उद्योग के भीतर और बाहरकृदोनों जगह समान आदर के पात्र बने रहे। धर्मेंद्र ने अपनी निजी और राजनीतिक जिंदगी में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। वे वर्ष 2004 में लोकसभा के लिए चुने गए और अपने तरीके से जनता की सेवा की। हालाँकि वे राजनीति में गहराई से सक्रिय नहीं रहे, लेकिन यह साफ समझ आता है कि वे समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझते थे। उनका चरित्र उतना ही सीधा और स्पष्ट था जितना उनका अभिनय। उनकी जीवनशैली की सादगी ने भी लोगों को हमेशा प्रभावित किया। मुंबई की भीड़भाड़ से दूर उनका फार्महाउस, धरती पर काम करना, खेतों को सींचना, पशुओं के साथ समय बितानाकृये सब उनकी आत्मा को सुकून देते थे। यह उस अभिनेता की तस्वीर है जो चमकते पर्दे से परे, असली जिंदगी में प्रकृति की गोद में अपने आप को पूरा महसूस करता था। यह गुण किसी अभिनेता में शायद ही देखने मिलता हो। उनका योगदान सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं। आज की पीढ़ी भी धर्मेंद्र की फिल्मों में वही ताजगी, वही मानवीय संवेदना और वही संवादशक्ति महसूस करती है, जो 40–50 साल पहले दर्शक महसूस करते थे। यह बहुत कम कलाकारों के हिस्से आता है कि उनकी फिल्मों की ताकत पीढ़ियों की सीमाएँ लांघ जाए। धर्मेंद्र यह विरासत अपने साथ लेकर नहीं गएय वे इसे समाज में छोड़ गए हैं।

आज जब हम उन्हें स्मरण करते हैं, तो उनके चेहरे की वह सहज मुस्कान तुरंत आँखों के सामने आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी किसी दृश्य की तैयारी कर रहे हों, या किसी इंटरव्यू में अपनी प्रसिद्ध विनम्रता के साथ कह रहे होंकृ"अरे, मैं कौन सा बड़ा कलाकार हूँ, बस अपनी कोशिश करता हूँ।" उनकी यह बात ही उन्हें बड़ा बनाती थी।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

क्कलिंग समाचार

राउरकेला, सोमवार 01 दिसंबर 2025 पृष्ठ-6

करीब चार लाख आयकरदाता मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे?

भुवनेश्वर ३०/११ (संवाददाता): राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत फर्जी राशन कार्डों की संज्या और अपात्र व्यक्तियों द्वारा मुज्त राशन का लाभ उठाने की स्पष्ट तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई हैए लेकिन खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि करीब चार लाख आयकरदाता मुज्त खाद्यान्न के लाभार्थी हैं। मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा जाल में शामिल लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए चल रहे ईकेवाईसी सत्यापन के दौरान पिछली बीजद सरकार द्वारा लाभार्थियों के चयन और अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड वितरित करने में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। पात्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा 41 लाख से अधिक लाभार्थियों का ईकेवाईसी सत्यापन अभी भी जारी है। बताया गया है कि नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करीब चार लाख लोगों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। जल्द ही स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी कि पिछली सरकार ने कितने अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड बांटे हैं।ष् मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों की स्थिति का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र सत्यापन के माध्यम से संदिग्ध सूची में सभी राशन कार्डों का सत्यापन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

फील्ड वेरिफिक्रेशन के बाद अपात्र व्यक्तियों को जारी किए गए राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। पात्रा ने कहा कि छह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग नए आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल खोलेगा। उन्होंने कहा कि फर्जी राशन कार्डों को खत्म करने के बाद नए कार्ड जारी किए जाएंगे।

बलांगीर में फर्जी खुफिया विभाग का भंडाफोड़

बलांगीर ३०/११ (संवाददाता):बलांगीर में एक फर्जी खुफिया विभाग का भंडाफोड़ हुआ है। जालसाज इस विभाग को छप्ठ यानी नेशनल इंटेलिजेंस ज्यूरो के नाम से चला रहे थे। वे अब तक फर्जी खुफिया विभाग की फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर लोगों से लाखों रुपए ठग चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसारए बलांगीर पुलिस को एक बड़ी सफ्लता मिली हैए जहां एक फर्जी खुफिया विभाग का भंडाफोड़ हुआ है। एनआईबी के नाम पर यह फर्जी विभाग लोगों से लाखों रुपये लूट रहा था और फर्जी नौकरी नियुक्ति पत्र मुहैया करा रहा था। पुलिस ने धोखाधड़ी में प्रयुक्त कई कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्कए फर्जी मुहरें, स्टाज्प और अन्य अवैध सामग्री जज़्त की है। इस सिलसिले में बलांगीर पुलिस ने राज्य के बाहर से 2 लोगों को गिरज़्तार किया है। जालसाजों ने एक फर्जी वेबसाइट खोल रखी थी और इसके जरिए काम कर रहे थे। मामले की आगे की जांच जारी है। एनआईबी के नाम पर यह फर्जी विभाग लोगों से लाखों रुपये लूट रहा था और फर्जी नौकरी नियुक्ति पत्र मुहैया करा रहा था।

इस्पात अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में डेंगू की रोकथाम पर जागरूकता सत्र आयोजित

राउरकेला ३०/११ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर अभियांत्रिकी विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा 19 जुलाई, 2025 को सेज़्टर-20 स्थित इस्पात अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का नेतृत्व उप मुज्य चिकित्सा अधिकारी (नगर अभियांत्रिकी-जन स्वास्थ्य), डॉ .दीपा लवंगारे ने किया जिन्होंने छात्रों को डेंगू के कारणों, लक्षणों और निवारक उपायों के बारे में जागरूक किया।

इस सत्र में लगभग 200 छात्रों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वच्छता बनाए रखने, मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को अपनाने के बारे में शिक्षित करना था। डॉ. लवंगारे ने सदियों पुरानी कहावत, इलाज से बेहतर रोकथाम है के महत्व पर ज़ोर दिया और छात्रों को अपने आसपास के वातावरण में सतर्क और ज़िज़्मेदार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. लवंगारे ने शीघ्र निदान और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप के महत्व को भी दर्शाया। यह पहल स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और रोग निवारण में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा थी। सहायक प्रबंधक (जन स्वास्थ्य), श्री रसानंद प्रधान ने समारोह का समन्वयन किया।

उल्लेखनीय है कि जन स्वास्थ्य इकाई स्टील टाउनशिप में डेंगू की रोकथाम पर व्यापक जागरूकता अभियान चला रही है। संयंत्र के 21 प्रशिक्षित डेंगू योद्धाओं की एक समर्पित टीम को घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया है, जिन्होंने अब तक लगभग 7000 क्वार्टरों का सर्वेक्षण किया है। मच्छरों के प्रजनन के स्रोत से निपटने के लिए, आवासीय और संवेदनशील क्षेत्रों में लार्वा-रोधी उपचार और इनडोर छिड़काव गतिविधियाँ की जा रही हैं। साथ ही, प्रजनन स्थलों को खत्म करने के लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक झाड़ी कटाई अभियान शुरू किए गए हैं।

ब्राह्मणी के बाद कोयल नदी घाट पर बालू माफ्या की नजर

राउरकेला ३०/११ (संवाददाता): सुदरगढ़ जिले के पानपोष अनुमंडल के पांच तहसील अंतर्गत 44 बालू घाट में से अधिकतर की लीज अवधि पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद बालू का खनन व परिवहन जारी है। तहसील की ओर से नीलामी में देर किए जाने से माफ्या व ठेकेदार घाट से बालू का अवैध रूप से उठाव कर मालामाल हो रहे हैं। तहसील अधिकारियों की ओर से नाम मात्र की छापेमारी कर जुर्माना लेकर छोड़ दिए जाने से अवैध कारोबारियों का हौसला बढ़ गया है। अब बालू माफ्या की नजर ब्राह्मणीए शंख के बाद कोयल नदी घाट से बालू खनन व तस्करी पर है। राउरकेला तहसील में सातए बिसरा में सातए कुआरमुंडा में 13ए लाठीकटा में आठए बीरमित्रपुर में नौ बालू घाट हैं। राउरकेला तहसील में ब्राह्मणी नदी पर तरककेरा.1ए तरकेरा.2ए तरकेरा.3ए कोयल नदी में तुमकेलाए लुआकेराए प्रधानपाली व सेज़्टर.16ए कोयलनगर बालूघाट हैं। इनमें से दो की नीलामी नहीं हुई है इनके बावजूद बालू का खनन व परिवहन जारी है।

इसी तरह बिसरा तहसील में जामसेरा.1ए जामसेरा.2ए उडसूए कुंडापोषए जोबाघाटए बड़बंबुआए मिटकुंदरी बालू घाट हैं। इसमें से केवल दो की नीलामी हुई है। शेष की लीज अवधि खत्म हो चुकी है पर बालू का खान पहले की तरह ही जारी है।

कुआरमुंडा तहसील में 13 में से बीजू बंधए पसराए जमुनानाकीए कुदाबेड़ा घाट से बालू ढुलाई की अनुमति है जबकि अन्य नौ की नीलामी होनी है। यहां से भी अवैध रूप से बालू का खनन व परिवहन जारी है। बीरमित्रपुर तहसील क्षेत्र में तेतरकेलाए गोपुरए लंकेइए जाहिरटोली घाट की नीलामी हुई है पर अन्य पांच की नीलामी नहीं हुई है। नीलामी के बगैर ही बालू की ढुलाई में दलालए अधिकारी व ठेकेदार शामिल हैं। निर्माण कार्य में बालू लगाने के साथ.साथ जगह.जगह बालू जमा कर रखा जा रहा है ताकि मांग के समय इसे अधिक दाम में बेचा जा सके।

ओडिशा हाई कोर्ट में सभी मामलों और डॉज़्यूमेंट्स की होगी, पोर्टल से कर सकेंगे केस फाइल

कटक ३०/११ (संवाददाता): 15 जुलाई तारीख से हाईकोर्ट में दायर होने वाली तमाम मामले और दाखिल किए जाने वाले कागजात यानी डॉज़्यूमेंट पूरी तरह से ई.फाइलिंग प्रक्रिया में होगा। इसको लेकर हाई कोर्ट की ओर से सोमवार को एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है।

ई.फाइलिंग रूल फॉर दी हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा 2024 के अनुसारए सभी मामले एवं तमाम कागजात ई.फाइलिंग व्यवस्था के द्वारा दाखिल होगी। यह बात विज्ञप्ति में स्पष्ट की गई है। निर्दिष्ट कुछ परिस्थितियों में वर्तमान के प्रचलित धारा में मामलों का फिजिकल फाइलिंग के लिए इजाजत दी जाएगी।

ई.फाइलिंग गवर्नेंस 3ण्0 पोर्टल को जाकर कोई भी ई.फाइलिंग कर सकेगा। इस बात का विज्ञप्ति में जिक्र किया गया है। अपने मामले और कागजातों की इस व्यवस्था तहत फाईलिंग करने में वकील और वकीलों के ज़्लर्क या महफ्लिों के लिए यह काफी आसान होगा।

उनके के लिए इस व्यवस्था को अधिक सहज करने के लिए हाई कोर्ट परिसर में स्कैनिंग सेंटर की स्थापना की गई है। मामलों के ई.फाइलिंग करने के लिए तथा इस प्रक्रिया के साथ अज़्यास में जुड़े रहने के लिए स्कैनिंग सेंटर के साथ.साथ ई.फाइलिंग काउंटर और ई.फेसिलिटेशन सेंटर सेवाओं को उपयोग करने के लिए वकील और वकीलों के ज़्लर्क से अनुरोध किया गया है।

इस व्यवस्था के चलते आगे से वह अपने घर से या फिर दज़्तर से या फिर किसी अलग जगह से हाई कोर्ट में मामला दायर कर सकेंगे। ई.फाइलिंग वर्जन 3 संबंधित यूजर मैन्युअल और वीडियो ट्यूटोरियल हाई कोर्ट वेबसाइट में उपलज़्ध है।

इससे ई.फाइलिंग वर्जन 3.0 पंजीकरण और दूसरे प्रक्रिया संबंधित जानकारी प्राप्त किया सकेंगा।

हम सब मिलकर प्रयास करें कि 2029 तक आरएसपी देश का सबसे कम लागत में इस्पात उत्पादन करने वाला संयंत्र बनें-आलोक वर्मा

राउरकेला ३०/११ (संवाददाता): आरएसपी के निदेशक प्रभारी, श्री आलोक वर्मा ने सभागार में आयोजित सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के 875वें सामूहिक संपर्क सभा को संबोधित करते हुए संयंत्र के कर्मीसमूह से कहा, आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि 2029 तक आरएसपी देश का सबसे कम लागत में इस्पात उत्पादन करने वाला संयंत्र बनें, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक (संकार्य), श्री बी आर पलाई, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार और कार्यपालक निदेशक (खान), श्री एम पी सिंह, भी मंच पर उपस्थित थे। मुज्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा) प्रभारी, डॉ. जे के आचार्य, कई मुज्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्षों के साथ-साथ खान सहित आरएसपी के विभिन्न विभागों के लगभग 500 कर्मचारी इस सत्र में शामिल हुए। आरएसपी में भारत का सर्वश्रेष्ठ इस्पात निर्माता बनने की क्षमता होने के अपने विश्वास पर बल देते हुए, श्री वर्मा ने कर्मचारियों से कोक की दर, कच्चे माल की लागत, खरीद लागत को और कम करने तथा कोक से हॉट मेटल के अनुपात में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि लोगों की सुरक्षा से बढ़ कर कुछ भी नहीं और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है । आरएसपी के कर्मचारियों की सराहना करते हुए, निदेशक प्रभारी ने कहा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले इस्पात निर्माता हैं। मैं आपको विज़ीय वर्ष की पहली तिमाही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले महीनों में यह गति और बढ़ेगी। श्री वर्मा ने इस अवसर पर आरएसपी पोर्टल में सामग्री प्रबंधन विभाग के डैशबोर्ड का भी उद्घाटन किया।

श्री तरुण मिश्र ने आरएसपी के कर्मचारियों को पहली तिमाही में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और टाउनशिप में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए संयंत्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्री पलाई ने प्रत्येक कर्मचारी से मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करके कार्यस्थल पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से साइटों का दौरा करने और सुरक्षा स्थितियों का जायज़ा लेने पर ज़ोर दिया। श्री अनिल कुमार ने सामग्री प्रबंधन विभाग पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें विपणन विभाग, प्रदर्शन मापदंडों और सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा की जा रही नई पहलों जैसे फेरो सिलिकॉन के मशीनीकृत नमूने और ज्यूआर कोडिंग का अवलोकन शामिल था। उन्होंने सामूहिक रूप से इन्वेंट्री नीति का उचित पालन करने का भी आग्रह किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री एम पी सिंह ने ओडिशा खान समूह द्वारा किए गए प्रयासों से लौह अयस्क उत्पादन में लौह तत्व की मात्रा में सुधार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा खान समूह 2030 तक 100 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन प्राप्त करने के भारत सरकार के लक्ष्य की पूर्ती हेतु लौह अयस्क आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। सत्र के दौरान, निदेशक प्रभारी ने विज़ वर्ष 2024-25 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए क्रमशः आरएमएचपी और एचएसएम-2 को लागत चैंपियन पुरस्कार प्रदान किए। सत्र का एक अन्य मुज्य आकर्षण वार्ता सत्र था, जिसमें विभिन्न विभागों और वर्गों के कर्मचारी उत्पादन, उत्पादकता, रखरखाव, सुरक्षा, ज्ञान वर्धन, स्वास्थ्य और टाउनशिप सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आगे आए। बातचीत के दौरान दिए गए सुझाव की गुणवज़ा से खुश होकर, निदेशक प्रभारी ने तीन कर्मचारियों को %सर्वश्रेष्ठ सुझावकर्ता% पुरस्कार प्रदान किए।

इससे पहले, सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के गायन के साथ हुई। इसके बाद विभिन्न प्रयासों, लक्ष्यों, उपलज़्धियों और नई सुरक्षा पहलों में पिछली तिमाही में आरएसपी के प्रदर्शन पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाया गया ‘स्टील जर्नी’ पर एक संगीत वीडियो प्रदर्शित किया गया । 874वें सामूहिक संपर्क सभा में प्राप्त सुझावों की कार्रवाई रिपोर्ट पर एक और वीडियो भी दिखाया गया। एडमिन सहयोगी (एचआर-एल एंड डी), सुश्री सत्यबती बेहरा ने कार्यक्रम का मंच सञ्चालन किया।